20 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य

1011. **श्री अखिलेश दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है,

(ख) देश में उक्त कार्यक्रम के संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है,

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम की कितनी बार समीक्षा की गई है, और

(घ) सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम को किन-किन मंत्रालयों में लागू किया है?

रेल, संसदीय कार्य, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम-1986 का लक्ष्य है (1) गरीबी उन्मूलन, (2) उत्पादकता बढ़ाना (3) आय की असमानताओं को कम करना, (4) सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को हटाना, (5) जीवन शैली में सुधार लाना।

20 सूत्री कार्यक्रम-86 के कार्यान्वयन का प्रबोधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कार्यक्रम संबंधित केन्द्रक मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इस कार्यक्रम का प्रबोधन करता है तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट और तय किए गए लक्ष्यों की तुलना में मदवार उपलब्धि को दर्शाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट बनाता है। यह प्रकाशित दस्तावेज संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। कार्यक्रम के अंतर्गत लाई गई मदों/परियोजनाओं की सूची इन प्रकाशित दस्तावेजों में उपलब्ध है।

(घ) 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे मंत्रालयों की सूची विवरण-1 में है।

(नीचे देखिए)

विवरण-I

20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे केन्द्रक मंत्रालय/विभाग

1. कृषि मंत्रालय
   (क) कृषि और सहकारिता विभाग
   (ख) पशु-पालन एवं डेयरी विकास विभाग
2. रक्षा मंत्रालय
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
4. खाद्य एवं उपभोक्ता मामले
   (क) उपभोक्ता मामले संबंधी विभाग
   (ख) खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग
5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
   (क) परिवार कल्याण विभाग
   (ख) स्वास्थ्य विभाग
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (क) शिक्षा विभाग
   (ख) महिला और बाल विकास विभाग
   (ग) युवा कार्य और खेल विभाग
7. उद्योग मंत्रालय
   (क) लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग
8. श्रम मंत्रालय
9. गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय
10. कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
11. विद्युत मंत्रालय
12. ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय
13. कपड़ा मंत्रालय
14. शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय
   (क) शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
15. जल संसाधन मंत्रालय
16. कल्याण मंत्रालय

Infrastructure Equalisation for North Eastern Region

1012. SHRI W. ANGAU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have any plan for bringing up the North-eastern region for their infrastructure equalisation with national level in the Ninth Five Year Plan;

(b) what are the items of plan formulation in which Government are giving stress for the socio, economic development of this region, on State-wise basis; and

(c) the steps to be taken up for resource mobilisation in this region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, PARLIAMENTRY AFFAIRS AND PLAN-